

Dr. Shyama Prasad Mukherjee University

Dept. of Commerce

M.COM SEM- 2

TOPIC- UNIT 2 PART-1

BY- HARSHA

## UNIT II: ECONOMIC REFORMS SINCE 1991

Since independence, India followed the **mixed economy framework** by combining the advantages of both capitalist and socialist (planned) economic system. This policy resulted in the establishment of various rules and laws, which were aimed at controlling and regulating the economy; became major hindrances in growth and development of the economy. However, some scholars state that increasing role of public sector in economic activities has helped Indian economy to:

स्वतंत्रता के बाद से, भारत ने पूंजीवादी और समाजवादी (नियोजित) आर्थिक व्यवस्था दोनों के लाभों को मिलाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे का पालन किया। इस नीति के परिणामस्वरूप विभिन्न नियमों और कानूनों की स्थापना हुई, जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को नियंत्रित और विनियमित करना था; अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास में प्रमुख बाधा बन गई। हालांकि, कुछ विद्वानों का कहना है कि आर्थिक गतिविधियों में सार्वजनिक क्षेत्र की बढ़ती भूमिका ने भारतीय अर्थव्यवस्था को निम्न में मदद की है:

- achieve growth in savings, बचत में वृद्धि को प्राप्त
- develop a diversified industrial sector which produces a variety of goods and एक विविध औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करता है और
- achieve food security through sustained expansion of agricultural output. कृषि उत्पादन के निरंतर विस्तार के माध्यम से खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना।

In 1991, the government of India initiated a series of economic reforms due to a financial crisis and pressure from international organisations like World Bank and IMF. **These reforms came to be known as the New Economic Policy (NEP)**. 1991 में, भारत सरकार ने वित्तीय संकट और विश्व बैंक और आईएमएफ जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के दबाव के कारण आर्थिक सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की। इन सुधारों को नई आर्थिक नीति (एनईपी) के रूप में जाना जाने लगा।

### Need for Economic Reforms/ आर्थिक सुधारों की आवश्यकता

1. **Fall in foreign exchange reserves/ विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट::** In 1991, India met with a foreign exchange or external debt crisis. 1991 में, भारत एक विदेशी मुद्रा या विदेशी ऋण संकट से मिला।

- a. The government was not able to make repayments on its borrowings from abroad./ सरकार विदेशों से अपने उधार पर पुनर्भुगतान करने में सक्षम नहीं थी।
- b. The **foreign exchange reserves declined** to a level that was not adequate- विदेशी मुद्रा भंडार उस स्तर तक गिर गया जो पर्याप्त नहीं था-
  - to finance imports for more than two weeks and दो सप्ताह से अधिक समय के लिए आयात के वित्तपोषण के लिए और
  - to pay the interest that needs to be paid to international lenders. अंतरराष्ट्रीय उधारदाताओं को भुगतान किए जाने वाले ब्याज का भुगतान करने के लिए।

2. **Financial crisis/ वित्तीय संकट:** The origin of the financial crisis can be traced from the **inefficient management of the Indian economy in the 1980s**. 1980 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था के अक्षम प्रबंधन से वित्तीय संकट की उत्पत्ति का पता लगाया जा सकता है।
- Development policies required that even though the revenues were very low, the government had to overshoot its revenue to meet challenges like unemployment, poverty and population explosion. The continued spending on development programmes of the government did not generate additional revenue. विकास नीतियों के लिए आवश्यक था कि राजस्व बहुत कम होने के बावजूद, सरकार को बेरोजगारी, गरीबी और जनसंख्या विस्फोट जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने राजस्व से अधिक खर्च करना पड़ा। सरकार के विकास कार्यक्रमों पर निरंतर खर्च से अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न नहीं हुआ।
  - Moreover, the government was not able to generate sufficient revenue from internal sources such as taxation. इसके अलावा, सरकार कराधान जैसे आंतरिक स्रोतों से पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करने में सक्षम नहीं थी।
  - The government was spending a large share of its income on areas which do not provide immediate returns such as the social sector and defence. सरकार अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा उन क्षेत्रों पर खर्च कर रही थी जो तत्काल रिटर्न प्रदान नहीं करते हैं जैसे कि सामाजिक क्षेत्र और रक्षा
  - The income from public sectors undertakings (PSUs) was also not very high to meet the growing expenditure. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) से होने वाली आय भी बढ़ते खर्च को पूरा करने के लिए बहुत अधिक नहीं थी।

Hence our foreign exchange, borrowed from other countries and international financial institutions, was spent on meeting consumption needs. इसलिए हमारी विदेशी मुद्रा, अन्य देशों और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से उधार ली गई, खपत की जरूरतों को पूरा करने पर खर्च की गई।

3. **Mounting government debts/ बढ़ते सरकारी कर्ज:** In the late 1980s, government expenditure began to exceed its revenue by such large margins that meeting the expenditure through borrowings became unsustainable. Moreover, no attempt was made to reduce such profligate government spending. 1980 के दशक के उत्तरार्ध में, सरकारी व्यय अपने राजस्व से इतने बड़े अंतर से अधिक होने लगा कि उधार के माध्यम से व्यय को पूरा करना असंभव हो गया। इसके अलावा, इस तरह के विपुल सरकारी खर्च को कम करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था।
4. **Adverse Balance of Payments/ प्रतिकूल भुगतान संतुलन:** Imports grew at a very high rate without matching growth of exports. Slow growth of exports was due to low quality and high prices of Indian goods in the international market. Also, no sufficient attention was given to boost exports to pay for the growing imports. निर्यात की समान वृद्धि के बिना आयात बहुत उच्च दर से बढ़ा। निर्यात की धीमी वृद्धि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय वस्तुओं की कम गुणवत्ता और उच्च कीमतों के कारण थी। इसके अलावा, बढ़ते आयात के भुगतान के लिए निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था।

5. **Rising prices of essential goods/ आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें:** The economic crisis in 1991 was further compounded by rising prices. Prices of many essential goods rose sharply due to inefficiencies in private as well as public sector production and high tariffs even on essential imports. 1991 में आर्थिक संकट बढ़ती कीमतों से और बढ़ गया था। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उत्पादन में अक्षमताओं और आवश्यक आयातों पर भी उच्च शुल्क के कारण कई आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ीं।

To manage the economic crisis in 1991, India approached the **International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)**, popularly known as **World Bank** and the **International Monetary Fund (IMF)** and received \$7 billion as loan. For availing the loan, India was required to liberalise and open up the economy by

- reducing the role of the government in many areas (or Liberalisation),
- removing restrictions on the private sector (or Privatisation) and
- removing trade restrictions between India and other countries (Globalisation).

India agreed to the conditions of World Bank and IMF and announced the **New Economic Policy (NEP) in July 1991**.

1991 में आर्थिक संकट का प्रबंधन करने के लिए, भारत ने पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD), जिसे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के रूप में जाना जाता है, से संपर्क किया और ऋण के रूप में \$7 बिलियन प्राप्त किए। ऋण प्राप्त करने के लिए, भारत को उदारीकरण और अर्थव्यवस्था को खोलने की आवश्यकता थी

- कई क्षेत्रों (या उदारीकरण) में सरकार की भूमिका को कम करना,
- निजी क्षेत्र (या निजीकरण) पर प्रतिबंध हटाना और
- भारत और अन्य देशों के बीच व्यापार प्रतिबंधों को हटाना (वैश्वीकरण)।

भारत विश्व बैंक और आईएमएफ की शर्तों पर सहमत हुआ और जुलाई 1991 में नई आर्थिक नीति (एनईपी) की घोषणा की।

The New Economic Policy consisted of wide-ranging economic reforms. The three broad components of NEP are – Liberalisation, Privatisation and Globalisation. The main aim of the policy was to create a more competitive environment in the economy and remove the barriers to entry and growth of firms. **This set of policies can broadly be classified into two groups: the stabilisation measures and the structural reform measures.**

नई आर्थिक नीति में व्यापक आर्थिक सुधार शामिल थे। एनईपी के तीन व्यापक घटक हैं - उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। नीति का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अधिक प्रतिस्पर्धी माहौल बनाना और फर्मों के प्रवेश और विकास की बाधाओं को दूर करना था। नीतियों के इस सेट को मोटे तौर पर दो समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है: स्थिरीकरण उपाय और संरचनात्मक सुधार उपाय।

### **Classification of New Economic Policy/ नई आर्थिक नीति का वर्गीकरण**

1. **Stabilisation measures** are short term measures, intended to correct some of the weaknesses that have developed in the balance of payments and to bring inflation under control. (E.g. Devaluation of rupee which means reduction in the value of rupee i.e. domestic currency in terms of foreign currency.) स्थिरीकरण उपाय अल्पकालिक उपाय हैं, जिनका उद्देश्य भुगतान संतुलन में विकसित कुछ कमजोरियों को दूर करना और मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाना है। (जैसे रुपये का अवमूल्यन जिसका अर्थ है रुपये के मूल्य में कमी यानी विदेशी मुद्रा के संदर्भ में घरेलू मुद्रा।)
2. **Structural reform policies** are long term measures, aimed at improving the efficiency of the economy and increasing its international competitiveness by removing the rigidities in various

segments of the Indian economy through a range of policies which fall under three heads viz. Liberalisation, Privatisation and Globalisation. संरचनात्मक सुधार नीतियां दीर्घकालिक उपाय हैं, जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की दक्षता में सुधार करना और भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कठोरता को दूर करके इसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है, जो कि तीन प्रमुखों के अंतर्गत आती है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण।

**Liberalisation:** It refers to the removal or reduction of government controls and restrictions from various sectors of the economy like industrial sector, financial sector, fiscal (tax) reforms, foreign exchange markets and trade and investment sectors for making the economy more competitive. उदारीकरण: यह अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, राजकोषीय (कर) सुधार, विदेशी मुद्रा बाजार और व्यापार और निवेश क्षेत्रों जैसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से सरकारी नियंत्रण और प्रतिबंधों को हटाने या घटाने को संदर्भित करता है।

**Need for Liberalisation:** Prior to 1991, there were large number of government restrictions on the entry and growth of private enterprises. Liberalisation was introduced to put an end to these restrictions and open various sectors of the economy.

उदारीकरण की आवश्यकता: 1991 से पहले, निजी उद्यमों के प्रवेश और विकास पर बड़ी संख्या में सरकारी प्रतिबंध थे। इन प्रतिबंधों को समाप्त करने और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को खोलने के लिए उदारीकरण की शुरुआत की गई थी।

### **Industrial Sector Reforms/ औद्योगिक क्षेत्र में सुधार:**

Before 1991, the industries were regulated in various ways: 1991 से पहले, उद्योगों को विभिन्न तरीकों से विनियमित किया जाता था:

- Industrial licensing was compulsory to start a firm, close a firm or to expand or diversify production. एक फर्म शुरू करने, एक फर्म को बंद करने या उत्पादन का विस्तार या विविधता लाने के लिए औद्योगिक लाइसेंस अनिवार्य था।
- Private sector was not allowed in many industries. कई उद्योगों में निजी क्षेत्र को अनुमति नहीं थी।
- Some goods were reserved only for small-scale industries. कुछ सामान केवल लघु उद्योगों के लिए आरक्षित थे।
- There was control on price fixation and distribution of certain selected industrial products. कुछ चुनिंदा औद्योगिक उत्पादों के मूल्य निर्धारण और वितरण पर नियंत्रण था।

The various measures under industrial policy reforms include/ औद्योगिक नीति सुधारों के तहत विभिन्न उपायों में शामिल हैं: :

- a. **Reduction in Industrial Licensing/ औद्योगिक लाइसेंसिंग में कमी:** Industrial licensing was **abolished** for almost all products except alcohol, cigarettes, hazardous chemicals, industrial explosives, electronics, aerospace, drugs शराब, सिगरेट, खतरनाक रसायन, औद्योगिक विस्फोटक, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस, ड्रग्स को छोड़कर लगभग सभी उत्पादों के लिए औद्योगिक लाइसेंस समाप्त कर दिया गया था।

- b. **De-reservation of public sector/ सार्वजनिक क्षेत्र का डी-आरक्षण:** The only industries which are now reserved for the public sector area part of defence equipment, atomic energy generation and railway transport. एकमात्र उद्योग जो अब सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं, वे रक्षा उपकरण, परमाणु ऊर्जा उत्पादन और रेलवे परिवहन का हिस्सा हैं।
- c. **De-reservation of small-scale industries/ लघु उद्योगों का अनारक्षण:** Many goods produced by small-scale industries have now been de-reserved. लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित कई वस्तुओं को अब गैर-आरक्षित कर दिया गया है।
- d. **Removal of price control/ मूल्य नियंत्रण हटाना:** In many industries, the market has been allowed to determine the prices. कई उद्योगों में बाजार को कीमतें तय करने की छूट दी गई है।

### **Financial Sector Reforms (Banking Sector Reforms): वित्तीय क्षेत्र सुधार (बैंकिंग क्षेत्र सुधार):**

(Before 1991 the RBI was regulator and it decides the amount of money that the banks can keep with themselves, fixes interest rates, nature of lending to various sectors, etc.) (1991 से पहले आरबीआई नियामक था और यह तय करता है कि बैंक कितनी राशि अपने पास रख सकता है, ब्याज दरें तय करता है, विभिन्न क्षेत्रों को उधार देने की प्रकृति आदि)

The reforms included under financial sector are: वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल सुधार हैं:

- a. The **role of RBI was reduced from regulator to facilitator** of financial sector. This means that the financial sector was allowed to take decisions on many matters without consulting the RBI.
  - b. The reform policies led to the **establishment of private sector banks**, Indian as well as private.
  - c. **Foreign investment limit in banks** was raised to around 50 percent.
  - d. Those banks which fulfil certain conditions have been given **freedom to set up new branches without the approval of the RBI** and rationalise their existing branch networks.
  - e. **Foreign Institutional Investors (FII)**, such as merchant bankers, mutual funds and pension funds **are now allowed to invest** in Indian financial markets.
- a. आरबीआई की भूमिका नियामक से वित्तीय क्षेत्र के सूत्रधार तक कम कर दी गई थी। इसका मतलब है कि वित्तीय क्षेत्र को आरबीआई से परामर्श किए बिना कई मामलों पर निर्णय लेने की अनुमति दी गई थी।
  - b. सुधार नीतियों ने निजी क्षेत्र के बैंकों की स्थापना की, भारतीय और साथ ही निजी।
  - c. बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर लगभग 50 प्रतिशत कर दिया गया है।
  - d. कुछ शर्तों को पूरा करने वाले बैंकों को आरबीआई की मंजूरी के बिना नई शाखाएं स्थापित करने और अपने मौजूदा शाखा नेटवर्क को युक्तिसंगत बनाने की स्वतंत्रता दी गई है।
  - e. विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई), जैसे मर्चेन्ट बैंकर, म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड अब भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश करने की अनुमति है।

**Financial Sector/ वित्तीय क्षेत्र:** Financial sector includes financial institutions such as commercial banks, investment banks, stock exchange operations and foreign exchange market. The financial sector in India is regulated through various norms and regulations by the Reserve Bank of India (RBI). The RBI decides the amount of money that the banks can keep with themselves, fixes interest rates, nature of lending to various sectors, etc. वित्तीय क्षेत्र में वित्तीय संस्थान जैसे वाणिज्यिक बैंक, निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज संचालन और विदेशी मुद्रा बाजार शामिल हैं। भारत में वित्तीय क्षेत्र को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा विभिन्न मानदंडों और विनियमों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। आरबीआई यह तय करता है कि बैंक कितनी राशि अपने पास रख सकता है, ब्याज दरें तय करता है, विभिन्न क्षेत्रों को उधार देने की प्रकृति आदि।

**Tax Reforms (or Fiscal Policy Reforms) कर सुधार (या राजकोषीय नीति सुधार):** Tax reforms are concerned with the reforms in government's taxation and public expenditure policies. (Government's

taxation and public expenditure policies are collectively known as its **fiscal policy.**) कर सुधार सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों में सुधारों से संबंधित हैं। (सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों को सामूहिक रूप से इसकी राजकोषीय नीति के रूप में जाना जाता है।)

### **Types of taxes:**

There are two types of taxes:

- (i) **Direct taxes** consist of taxes on incomes of individuals, as well as, profits of business enterprises. The burden of such taxes cannot be shifted. E.g. Income tax, wealth tax, corporate tax etc.
- (ii) **Indirect taxes** are the taxes levied on commodities and services. The burden of these taxes can be shifted to the consumers. E.g. GST, Value Added Tax (VAT) etc.

(Before 1990, tax rates were very high for both direct and indirect taxes)

The major tax reforms made are:

- a. Since 1991, there has been a **continuous reduction in the taxes on individual incomes** as it was felt that high rates of income tax were an important reason for tax evasion.
- b. The **rate of corporation tax**, which was very high earlier, **has been gradually reduced.**
- c. Efforts have also been made to **reform the indirect taxes**, in order to facilitate the **establishment of a common national market** for goods and commodities.
- d. In order to encourage better compliance on the part of taxpayers, many **tax procedures** have been **simplified** and the **rates also substantially lowered.**
- e. Recently, the Indian Parliament passed a law, Goods and Services Act 2016, to simplify and introduce a unified indirect tax system in India. This law came into effect from July 2017.

### **करों के प्रकार:**

कर दो प्रकार के होते हैं:

- (i) प्रत्यक्ष करों में व्यक्तियों की आय के साथ-साथ व्यावसायिक उद्यमों के मुनाफे पर कर शामिल होते हैं। ऐसे करों के बोझ को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। उदा. आयकर, संपत्ति कर, कॉर्पोरेट कर आदि।
- (ii) अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाने वाले कर हैं। इन करों का बोझ उपभोक्ताओं पर डाला जा सकता है। उदा. जीएसटी, मूल्य वर्धित कर (वैट) आदि।

(1990 से पहले, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों के लिए कर की दरें बहुत अधिक थीं) किए गए प्रमुख कर सुधार इस प्रकार हैं:

- a. 1991 के बाद से, व्यक्तिगत आय पर करों में लगातार कमी आई है क्योंकि यह महसूस किया गया था कि कर चोरी का एक महत्वपूर्ण कारण आयकर की उच्च दरें थीं।
- b. निगम कर की दर, जो पहले बहुत अधिक थी, धीरे-धीरे कम कर दी गई है।
- c. वस्तुओं और वस्तुओं के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय बाजार की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए अप्रत्यक्ष करों में सुधार के भी प्रयास किए गए हैं।
- d. करदाताओं की ओर से बेहतर अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए, कई कर प्रक्रियाएं की गई हैं सरलीकृत और दरों में भी काफी कमी आई है।
- e. हाल ही में, भारतीय संसद ने भारत में एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने और शुरू करने के लिए एक कानून, वस्तु और सेवा अधिनियम 2016 पारित किया। यह कानून जुलाई 2017 से लागू हुआ था।

Note: ‘**Goods and Services Tax**’ is a comprehensive **Indirect Tax** which has replaced many indirect taxes in India. The Goods and Services Tax Act was passed in the parliament on 29<sup>th</sup> March, 2017 to simplify and introduce a unified indirect tax system in India. The Act came into effect in 1<sup>st</sup> July, 2017. It is a comprehensive, multi-stage, destination-based tax that is levied on every value addition. GST has been identified as one of the most important tax reforms post-independence. The government of India implemented GST following the credo of ‘**One Nation and One Tax**’ and wanting a unified market in order to ensure the smooth flow of goods and services across the country. GST has replaced 17 indirect taxes (like Value Added Tax, Service Tax, Excise duty, Sales Tax etc) 23 cesses of the Centre and States, thereby eliminating the need for filing multiple returns and investments. It has rationalised the tax treatment of goods and services along the supply chain from producers to consumers.

**Foreign Exchange Reforms:** (Before 1991, Fixed exchange rate system was followed by the RBI.)

The major reforms made in the foreign exchange market are:

- a) In 1991, as an immediate measure to resolve the balance of payment crisis, **the rupee was devalued** against foreign currencies. (Devaluation refers to reduction in the value of domestic currency with respect to foreign currency.) This led to increase in the inflow of foreign exchange by making **exports cheaper** and more competitive.
- b) It also led to freeing the determination of rupee value in the foreign exchange market from government control. Now markets determine exchange rates based on the demand and supply of foreign exchange.

**Trade and investment Policy Reforms:** (Before 1991, **India was following Import substitution policy with high tariffs and quotas**-a regime of quantitative restrictions on imports. These policies reduced efficiency and competitiveness which led to the slow growth of the manufacturing sector.)

**Objective:** To increase international competitiveness of industrial production and also **foreign investments and technology** into the economy. The aim was to **promote the efficiency of local industries and adoption of modern technologies.**

**The important trade and investment policy reforms include:**

- a) **Dismantling of quantitative restrictions (Quotas) on imports and exports-** Quantitative restrictions on imports of manufactured consumer goods and agricultural products were also fully removed from April 2001.
- b) **Reduction tariff rates**– Export duties have been removed to increase the competitive position of Indian goods in the international markets and import duties have also been reduced.
- c) **Removal of licensing procedures for imports** – Import licensing was abolished except in case of hazardous and environmentally sensitive industries.

**विदेशी मुद्रा सुधार: (1991 से पहले, आरबीआई द्वारा निश्चित विनिमय दर प्रणाली का पालन किया गया था।)**

विदेशी मुद्रा बाजार में किए गए प्रमुख सुधार हैं:

- a) 1991 में, भुगतान संतुलन संकट को हल करने के लिए तत्काल उपाय के रूप में, विदेशी मुद्राओं के मुकाबले रुपये का अवमूल्यन किया गया था। (अवमूल्यन का तात्पर्य विदेशी मुद्रा के संबंध में घरेलू मुद्रा के मूल्य में कमी से है।) इससे निर्यात को सस्ता और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाकर विदेशी मुद्रा के प्रवाह में वृद्धि हुई।
- b) इसने विदेशी मुद्रा बाजार में रुपये के मूल्य के निर्धारण को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया। अब बाजार

विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति के आधार पर विनिमय दरों का निर्धारण करते हैं।

व्यापार और निवेश नीति सुधार: (1991 से पहले, भारत उच्च टैरिफ और कोटा के साथ आयात प्रतिस्थापन नीति का पालन कर रहा था-आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों का एक शासन। इन नीतियों ने दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को कम कर दिया जिससे विनिर्माण क्षेत्र की धीमी वृद्धि हुई।)

उद्देश्य: औद्योगिक उत्पादन की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता और अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी को बढ़ाना। इसका उद्देश्य स्थानीय उद्योगों की दक्षता को बढ़ावा देना और आधुनिक तकनीकों को अपनाना था। महत्वपूर्ण व्यापार और निवेश नीति सुधारों में शामिल हैं:

- आयात और निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों (कोटा) को समाप्त करना- निर्मित उपभोक्ता वस्तुओं और कृषि उत्पादों के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध भी अप्रैल 2001 से पूरी तरह से हटा दिए गए थे।
- टैरिफ दरों में कमी- अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धी स्थिति बढ़ाने के लिए निर्यात शुल्क हटा दिए गए हैं और आयात शुल्क भी कम कर दिया गया है।
- आयात के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को हटाना - खतरनाक और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील उद्योगों को छोड़कर आयात लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया था।

**Privatisation/ निजीकरण:** It implies shedding of the ownership or management of a government owned enterprise and its transfer to the private sector. इसका तात्पर्य सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम के स्वामित्व या प्रबंधन को छोड़ना और इसे निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करना है।

**Privatisation can be done in two ways:** निजीकरण दो तरह से किया जा सकता है:

- by withdrawal of the government from ownership and management of public sector companies (Disinvestment)  
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के स्वामित्व और प्रबंधन से सरकार की वापसी (विनिवेश)
- by outright sale of public sector companies (Complete privatization) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की एकमुश्त बिक्री द्वारा (पूर्ण निजीकरण)

Disinvestment: Privatisation of the public sector undertaking by selling off part of the equity of PSEs to the private sector/ public is known as disinvestment.

Types of disinvestment:

- Minority disinvestment: A minority disinvestment is one such that, at the end of it, the government retains a majority stake in the company, typically greater than 51%, thus ensuring management control.  
E.g. NTPC (National Thermal Power Corporation)
- Majority Disinvestment: A majority disinvestment is one in which the government, post disinvestment, retains a minority stake in the company i.e. it sells off a majority stake E.g. BALCO sale to Sterlite.
- Complete privatisation: It is a form of majority disinvestment wherein 100% control of the company is passed on to a buyer. Example: Modern Bread, ITDC Hotels.

Note: \* Strategic Disinvestment Sale: It refers to the sale of 51% or more stake of a PSU to the private sector who bids the highest with the objective of improving efficiency so the management control is with strategic partner.

विनिवेश: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की इक्विटी का



हिस्सा बेचकर निजीकरण को विनिवेश के रूप में जाना जाता है।

विनिवेश के प्रकार:

1. अल्पसंख्यक विनिवेश: एक अल्पसंख्यक विनिवेश एक ऐसा है, जिसके अंत में, सरकार कंपनी में बहुमत हिस्सेदारी रखती है, आमतौर पर 51% से अधिक, इस प्रकार प्रबंधन नियंत्रण सुनिश्चित करती है।  
उदा. एनटीपीसी (राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम)
2. बहुसंख्यक विनिवेश: बहुसंख्यक विनिवेश वह है जिसमें सरकार, विनिवेश के बाद, कंपनी में अल्पमत हिस्सेदारी रखती है यानी वह बहुमत हिस्सेदारी बेचती है। स्टरलाइट को बाल्को की बिक्री।
3. पूर्ण निजीकरण: यह बहुसंख्यक विनिवेश का एक रूप है जिसमें कंपनी का 100% नियंत्रण खरीदार को दिया जाता है।  
उदाहरण: मॉडर्न ब्रेड, आईटीडीसी होटल।

नोट: \* रणनीतिक विनिवेश बिक्री: यह एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की 51% या उससे अधिक हिस्सेदारी की बिक्री को संदर्भित करता है, जो दक्षता में सुधार के उद्देश्य से उच्चतम बोली लगाता है, इसलिए प्रबंधन नियंत्रण रणनीतिक भागीदार के पास है।

**Purpose of privatisation/ disinvestment: According** to the government the purpose of sale was mainly to-

- a. improve financial discipline and facilitate modernisation.
- b. It was also felt that private capital and managerial capabilities would be effectively utilized to improve the performance of the PSU's.
- c. It was felt that privatisation could provide strong impetus (encouragement) to the inflow of FDI.

**निजीकरण/विनिवेश का उद्देश्य: सरकार के अनुसार बिक्री का उद्देश्य मुख्य रूप से था-**

- a. वित्तीय अनुशासन में सुधार और आधुनिकीकरण की सुविधा।
- b. यह भी महसूस किया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रदर्शन में सुधार के लिए निजी पूंजी और प्रबंधकीय क्षमताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाएगा।
- c. यह महसूस किया गया कि निजीकरण एफडीआई के प्रवाह को मजबूत प्रोत्साहन (प्रोत्साहन) प्रदान कर सकता है।

### **Navratnas (profit making PSU's)**

- In order to improve efficiency of PSUs, infuse professionalism and enable them to compete more effectively in the liberalised global environment, the government choose nine PSUs and declared them as maharatnas, navratnas and miniratnas
- They were given greater managerial and operational autonomy in taking various decisions to run the company efficiently and thus increase their profits.
- Greater operational, financial and managerial autonomy has also been granted to profit making enterprises referred to as miniratnas
- Few examples of public enterprises with their status are as follows
  - (i) Maharatnas - Indian Oil Corporation (IOCL), Steel Authority of India Limited (SAIL)
  - (ii) Navratnas - Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Mahanagar Telephone Nigam Limited (MTNL)
  - (iii) Miniratnas - Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL), Airport Authority of India (AAI) and Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited (IRCTC).

Effect: The granting of Navratnas status resulted in better performances of these companies. Of late the government has decided to retain them in the public sector and enables them to expand themselves in the global market and raise resources by themselves from financial markets.

## नवरत्न

- सार्वजनिक उपक्रमों की दक्षता में सुधार करने, व्यावसायिकता को बढ़ावा देने और उन्हें उदार वैश्विक वातावरण में अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाने के लिए, सरकार ने नौ सार्वजनिक उपक्रमों को चुना और उन्हें महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न घोषित किया।
  - कंपनी को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए विभिन्न निर्णय लेने में उन्हें अधिक प्रबंधकीय और परिचालन स्वायत्तता दी गई और इस प्रकार उनके मुनाफे में वृद्धि हुई।
  - लाभ कमाने वाले उद्यमों को अधिक से अधिक परिचालन, वित्तीय और प्रबंधकीय स्वायत्तता प्रदान की गई है जिन्हें मिनीरत्न कहा जाता है
  - सार्वजनिक उद्यमों के कुछ उदाहरण उनकी स्थिति के साथ इस प्रकार हैं
    - (i) महारत्न - इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसीएल), स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)
    - (ii) नवरत्न - हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल), महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)
    - (iii) मिनीरत्न - भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)।
- प्रभाव: नवरत्न का दर्जा देने से इन कंपनियों का प्रदर्शन बेहतर हुआ। हाल ही में सरकार ने उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में बनाए रखने का फैसला किया है और उन्हें वैश्विक बाजार में खुद का विस्तार करने और वित्तीय बाजारों से स्वयं संसाधन जुटाने में सक्षम बनाता है।

**Globalisation/ वैश्वीकरण/ :** Globalisation means integrating the economy of the country with the world economy through removal of barriers on international trade and capital movements. वैश्वीकरण का अर्थ है अंतरराष्ट्रीय व्यापार और पूंजी आंदोलनों पर बाधाओं को दूर करके देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना।

- It is a complex phenomenon. यह एक जटिल घटना है।
- It is an outcome of the set of various policies that are aimed at transforming the world towards greater interdependence and integration. यह विभिन्न नीतियों के समूह का परिणाम है जिसका उद्देश्य दुनिया को अधिक से अधिक अन्योन्याश्रयता और एकीकरण की ओर बदलना है।
- It involves creation of network and activities transcending economic, social and geographical boundaries. इसमें आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं से परे नेटवर्क और गतिविधियों का निर्माण शामिल है।
- In short, Globalisation implies turning the world into one whole or creating a borderless world. संक्षेप में, वैश्वीकरण का अर्थ है दुनिया को एक पूरे में बदलना या एक सीमाहीन दुनिया बनाना।

**Outsourcing:** Outsourcing refers to the hiring of regular services by a company from external sources, mostly from other countries, which was previously provided internally or from within the country. E.g. legal advice, computer service, advertisement, security- each provided by respective departments of the company.

➤ Outsourcing is one of the important outcomes of the globalisation process.

- **Outsourcing has intensified in recent times** because of:
  - a. The **growth of fast modes of communication**, particularly the growth of Information Technology (IT).
  - b. With the help of modern telecommunication links including the internet, the text, voice and visual data in respect of these **services is digitalised and transmitted** in real time over continents and national boundaries.
- **Factors that have made India one of the favourite outsourcing destination in the post reform period are:**
  - a. Availability of skilled manpower in India and
  - b. the low wage rates.
- **Some of the services outsourced to India include:**
  - a. Voice-based business processes (popularly known as BPO or call centres)
  - b. Record keeping
  - c. Accountancy
  - d. Banking services
  - e. Music recordings
  - f. Film editing
  - g. Book transcription
  - h. Clinical advice etc

With increasing population and government's inability to provide employment, **outsourcing services** have proved to be a **boon for countries like India which has skilled manpower available at cheaper rates**. Thus, India has been benefited from outsourcing in terms of **generating employment opportunities** as well as it **contributes to the GDP and foreign exchange reserves** of our country.

**The developed countries are opposing it** because the domestic workers have been replaced by the workers in developing countries. It has resulted in the loss of jobs in favour of developing countries. The domestic workers are struggling to find jobs especially with low skills. This is leading to inequalities between the highly skilled persons and the lower ones (as highly skilled persons are willing to work at lower wages).

**Effects of Globalisation:** The process of globalisation through liberalisation and privatisation policies has produced positive as well as negative results both for India and other countries.

**Positive effects:** Globalisation resulted in -

- a. greater access to global markets;
- b. high (advanced) technology and

- c. increased possibility of large industries of developing countries to become important players in the international arena.

Negative effects: Globalisation has been criticised by some scholars because according to them:

- a. Globalisation is a strategy of the developed countries to expand their markets in other countries.
- b. It has compromised the welfare and identity of people belonging to poor countries.
- c. Market-driven globalisation has widened the disparities among nations and people.

**आउटसोर्सिंग:** आउटसोर्सिंग का तात्पर्य बाहरी स्रोतों से एक कंपनी द्वारा नियमित सेवाओं की भर्ती करना है, ज्यादातर अन्य देशों से, जो पहले आंतरिक रूप से या देश के भीतर से प्रदान की जाती थी। उदा. कानूनी सलाह, कंप्यूटर सेवा, विज्ञापन, सुरक्षा- प्रत्येक कंपनी के संबंधित विभागों द्वारा प्रदान किया जाता है।

आउटसोर्सिंग वैश्वीकरण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक है।

• हाल के दिनों में आउटसोर्सिंग तेज हो गई है क्योंकि:

- a. संचार के तीव्र साधनों का विकास, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का विकास।
- b. इंटरनेट सहित आधुनिक दूरसंचार लिंक की मदद से, इन सेवाओं के संबंध में पाठ, आवाज और दृश्य डेटा को डिजिटल रूप दिया जाता है और महाद्वीपों और राष्ट्रीय सीमाओं पर वास्तविक समय में प्रसारित किया जाता है।

• ऐसे कारक जिन्होंने सुधार के बाद भारत को पसंदीदा आउटसोर्सिंग गंतव्यों में से एक बना दिया है अवधि हैं:

- a. भारत में कुशल जनशक्ति की उपलब्धता और
- b. कम मजदूरी दर।

• भारत को आउटसोर्स की गई कुछ सेवाओं में शामिल हैं:

- a. आवाज आधारित व्यावसायिक प्रक्रियाएं (जिसे बीपीओ या कॉल सेंटर के नाम से जाना जाता है)
- b. रिकॉर्ड रखना
- c. लेखाकर्म
- d. बैंकिंग सेवाएं
- e. संगीत रिकॉर्डिंग
- f. फिल्म का संपादन
- g. पुस्तक प्रतिलेखन
- h. नैदानिक सलाह आदि

बढ़ती जनसंख्या और रोजगार प्रदान करने में सरकार की अक्षमता के साथ, आउटसोर्सिंग सेवाएं भारत जैसे देशों के लिए वरदान साबित हुई हैं, जिनके पास सस्ती दरों पर कुशल जनशक्ति उपलब्ध है। इस प्रकार, भारत को रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ-साथ हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद और विदेशी मुद्रा भंडार में योगदान देने के मामले में आउटसोर्सिंग से लाभ हुआ है।

विकसित देश इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि विकासशील देशों में घरेलू कामगारों की जगह कामगारों ने ले ली है। इसके परिणामस्वरूप विकासशील देशों के पक्ष में नौकरियों का नुकसान हुआ है। घरेलू कामगार विशेष रूप से कम कौशल वाले रोजगार खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह अत्यधिक कुशल व्यक्तियों और निचले लोगों के बीच असमानताओं को जन्म दे रहा है (क्योंकि अत्यधिक कुशल व्यक्ति कम मजदूरी पर काम करने के इच्छुक हैं)।

वैश्वीकरण के प्रभाव: उदारीकरण और निजीकरण नीतियों के माध्यम से वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने भारत और अन्य देशों दोनों के लिए सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम दिए हैं।

सकारात्मक प्रभाव: वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप -

- a. वैश्विक बाजारों तक अधिक पहुंच;
- b. उच्च (उन्नत) प्रौद्योगिकी और
- c. विकासशील देशों के बड़े उद्योगों के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने की संभावना बढ़ गई।

नकारात्मक प्रभाव: वैश्वीकरण की कुछ विद्वानों ने आलोचना की है क्योंकि उनके अनुसार:

- ए। वैश्वीकरण अन्य देशों में अपने बाजारों का विस्तार करने के लिए विकसित देशों की एक रणनीति है।
- बी। इसने गरीब देशों के लोगों के कल्याण और पहचान से समझौता किया है।
- सी। बाजार संचालित वैश्वीकरण ने राष्ट्रों और लोगों के बीच असमानताओं को बढ़ा दिया है।

**World Trade Organisation (WTO):** WTO was founded in 1995 as the successor organisation to the General Agreement on Trade and Tariff (GATT). GATT was established in 1948 with 23 countries as the global trade organisation to administer all multilateral trade agreements by providing equal opportunities to all countries in the international market for trading purposes.

**Aim (Functions) of WTO:**

- a. To establish a rule-based trading regime in which nations cannot place arbitrary restrictions on trade.
- b. To enlarge production and trade of services.
- c. To ensure optimum utilisation of world resources.
- d. To protect the environment.
- e. To facilitate international trade (bilateral and multilateral) through removal of tariff as well as non-tariff barriers and providing greater market access to all member countries.

**Relation between WTO and India:** As an important member of WTO, India has been in the forefront of framing fair global rules, regulations and safeguards and advocating the interests of the developing world. India has kept its commitments towards liberalisation of trade, made in the WTO, by removing quantitative restrictions on imports and reducing tariff rates.

Some scholars question the usefulness of India being a member of WTO. According to them:

- a. A major volume of international trade occurs among the developed nations.
- b. Developing countries feel cheated as they are forced to open their markets for developed countries but are not allowed to access to the markets of developed countries.

**विश्व व्यापार संगठन (WTO):** WTO की स्थापना 1995 में व्यापार और टैरिफ पर सामान्य समझौते (GATT) के उत्तराधिकारी संगठन के रूप में हुई थी। GATT की स्थापना 1948 में 23 देशों के साथ वैश्विक व्यापार संगठन के रूप में की गई थी, जो व्यापारिक उद्देश्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सभी देशों को समान अवसर प्रदान करके सभी बहुपक्षीय व्यापार समझौतों को संचालित करता है।

**विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य (कार्य):**

- a. एक नियम-आधारित व्यापार व्यवस्था स्थापित करना जिसमें राष्ट्र व्यापार पर मनमानी प्रतिबंध नहीं लगा सकते।
- b. सेवाओं के उत्पादन और व्यापार को बढ़ाना।
- c. विश्व संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना।
- d. पर्यावरण की रक्षा के लिए।
- e. टैरिफ के साथ-साथ गैर-टैरिफ बाधाओं को हटाने और सभी सदस्य देशों को अधिक से अधिक बाजार पहुंच प्रदान करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (द्विपक्षीय और बहुपक्षीय) को सुविधाजनक बनाना।

**विश्व व्यापार संगठन और भारत के बीच संबंध:** विश्व व्यापार संगठन के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, भारत निष्पक्ष वैश्विक नियमों, विनियमों और सुरक्षा उपायों को तैयार करने और विकासशील दुनिया के हितों की वकालत करने में सबसे

आगे रहा है। भारत ने आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाकर और टैरिफ दरों को कम करके, विश्व व्यापार संगठन में किए गए व्यापार के उदारीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को रखा है।

कुछ विद्वान विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होने के नाते भारत की उपयोगिता पर सवाल उठाते हैं। उनके अनुसार:

- a. विकसित देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बड़ा हिस्सा होता है।
- b. विकासशील देश ठगा हुआ महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें विकसित देशों के लिए अपने बाजार खोलने के लिए मजबूर किया जाता है लेकिन उन्हें विकसित देशों के बाजारों तक पहुंचने की अनुमति नहीं है।

### **Indian Economy During Reforms: An Assessment:**

#### **Positive effects of reforms:**

1. The **growth of GDP increased from 5.6% during 1980-91 to 8.2 % during 2007-12**. During the reform period, the growth of agriculture has declined, while the industrial sector reported fluctuations, the growth of the service sector has gone up. This indicates that **this growth is mainly driven by growth in the service sector**.
2. The **foreign investment**, which includes foreign direct investment (FDI) and foreign institutional investment (FII) **has increased** from about US \$100 million in 1990-91 to US \$ 36 billion in 2016-17.
3. There has been **an increase in the foreign exchange reserves** from about US \$ 6 billion in 1990-91 to about US \$ 321 billion in 2014-15. India is one of the largest foreign exchange reserve holders in the world.
4. India is seen as a **successful exporter of auto parts, engineering goods, IT software and textiles** in the reform period.
5. **Rising prices** have also been **kept under control**.

सुधारों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था: एक आकलन:

#### **सुधारों के सकारात्मक प्रभाव:**

1. सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 1980-91 के दौरान 5.6% से बढ़कर 2007-12 के दौरान 8.2% हो गई। सुधार अवधि के दौरान, कृषि के विकास में गिरावट आई है, जबकि औद्योगिक क्षेत्र में उतार-चढ़ाव की सूचना दी गई है, सेवा क्षेत्र की वृद्धि बढ़ी है। यह इंगित करता है कि यह वृद्धि मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र में वृद्धि से प्रेरित है।
2. विदेशी निवेश, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और विदेशी संस्थागत निवेश (एफआईआई) शामिल हैं, 1990-91 में लगभग 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2016-17 में 36 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।
3. विदेशी मुद्रा भंडार 1990-91 में लगभग 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2014-15 में लगभग 321 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। भारत दुनिया के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार धारकों में से एक है।
4. भारत को सुधार अवधि में ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग सामान, आईटी सॉफ्टवेयर और टेक्सटाइल के सफल निर्यातक के रूप में देखा जाता है।
5. बढ़ती कीमतों को भी नियंत्रण में रखा गया है

**Negative effects of reforms/ सुधारों के नकारात्मक प्रभाव:** The NEP has been widely criticised for not being able to address some of the basic problems facing our economy especially in the areas of employment, agriculture, industry, infrastructure development and fiscal management. विशेष रूप से रोजगार, कृषि, उद्योग, बुनियादी ढांचे के विकास और वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्रों में हमारी अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली कुछ बुनियादी समस्याओं को दूर करने में सक्षम नहीं होने के लिए एनईपी की व्यापक रूप से आलोचना की गई है।

1. **Growth and Employment/ विकास और रोजगार** - Though the GDP growth rate has increased in the reform period, scholars point out that the reform led growth has not generated sufficient employment opportunities in the country other than the service sector. This is known as '**Jobless growth**'. हालांकि सुधार की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में वृद्धि हुई है, विद्वानों का कहना है कि सुधार के नेतृत्व वाली वृद्धि ने सेवा क्षेत्र के अलावा देश में पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा नहीं किए हैं। इसे रोजगार रहित विकास के रूप में जाना जाता है।
2. **Reforms in Agriculture/ कृषि में सुधार** -- Reforms have not been able to benefit agriculture. **The growth rate in the agriculture sector has been decelerating in the reform period** because: सुधारों से कृषि को कोई लाभ नहीं हुआ है। सुधार की अवधि में कृषि क्षेत्र की विकास दर में गिरावट आ रही है क्योंकि:
  - a. Public investment in agriculture sector especially in infrastructure, which includes irrigation, power, roads, market linkages and research and extension has fallen in the reform period. कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निवेश, जिसमें सिंचाई, बिजली, सड़कें, बाजार संपर्क और अनुसंधान और विस्तार शामिल हैं, सुधार अवधि में गिर गया है।
  - b. The removal of fertiliser subsidy has led to increase in the cost of production, which has severely affected small and marginal farmers. उर्वरक सब्सिडी को हटाने से उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है, जिससे छोटे और सीमांत किसान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।
  - c. A number of policy changes such as reduction in import duties on agricultural products, removal of minimum support price and lifting of quantitative restrictions on agricultural products have adversely affected Indian farmers as they have to face increased international competition. कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क में कमी, न्यूनतम समर्थन मूल्य को हटाने और कृषि उत्पादों पर मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने जैसे कई नीतिगत परिवर्तनों ने भारतीय किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है क्योंकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।
  - d. The export-oriented policy strategies in agriculture have resulted in a shift from production of food grains for the domestic market towards production of cash crops for exports thereby putting immense pressure on prices of food grains. कृषि में निर्यात-मुखी नीतिगत रणनीतियों के परिणामस्वरूप घरेलू बाजार के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन से निर्यात के लिए नकदी फसलों के उत्पादन की ओर रुख हुआ है, जिससे खाद्यान्नों की कीमतों पर अत्यधिक दबाव पड़ा है।
3. **Reforms in Industry: Industrial growth has also recorded a slowdown during the reform period** because of decreasing demand of industrial products due to various reasons such as:
 

**उद्योग में सुधार:** सुधार अवधि के दौरान औद्योगिक विकास में भी मंदी दर्ज की गई है विभिन्न कारणों से औद्योगिक उत्पादों की घटती मांग के कारण जैसे:

  - a. Domestic manufacturers are facing competition from cheaper imports, which have replaced the demand for domestic goods.
  - b. The infrastructure facilities, including power supply, have remained inadequate due to lack of investment.
  - c. A developing country like India still does not have access to developed countries' markets because of non- tariff barriers. (For e.g. Although all quota restrictions on exports of textiles and clothing

have been removed in India, USA has not removed their quota restrictions on import of textiles from India and China.)

- a. घरेलू निर्माताओं को सस्ते आयात से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, जिसने घरेलू सामानों की मांग को बदल दिया है।
- b. निवेश की कमी के कारण बिजली आपूर्ति सहित बुनियादी सुविधाएं अपर्याप्त बनी हुई हैं।
- c. भारत जैसे विकासशील देश की अभी भी गैर-टैरिफ बाधाओं के कारण विकसित देशों के बाजारों तक पहुंच नहीं है। (उदाहरण के लिए, हालांकि भारत में वस्त्रों और कपड़ों के निर्यात पर सभी कोटा प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत और चीन से वस्त्रों के आयात पर अपने कोटा प्रतिबंधों को नहीं हटाया है।)

4. **Effect of disinvestment:** The assets of PSEs have been undervalued and sold to the public sector. This means that there has been **a substantial loss to the government**. Moreover, the proceeds from disinvestment were used to offset the shortage of government revenues rather than using it for the development of PSEs and building social infrastructure in the country.

4. विनिवेश का प्रभाव: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संपत्ति का कम मूल्यांकन किया गया है और सार्वजनिक क्षेत्र को बेचा गया है। यानी सरकार को काफी नुकसान हुआ है। इसके अलावा, विनिवेश से प्राप्त आय का उपयोग सरकारी राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए किया गया था, न कि इसका उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विकास और देश में सामाजिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया गया था।

5. **Fiscal Policy and Reforms:** Economic reforms have placed limits on the growth of public expenditure, especially in social sectors.

- a. The tax reductions in the reform period, aimed at yielding larger revenue and to curb tax evasion, have **not resulted in increase in tax revenue** for the government.
- b. The reform policies involving tariff reduction have **reduced the scope for raising revenue through custom duties**.
- c. **Tax incentives** provided to foreign investors to attract foreign investment, **has further reduced the scope for raising tax revenues**.

This has a negative impact on developmental and welfare expenditure

5. **राजकोषीय नीति और सुधार:** आर्थिक सुधारों ने सार्वजनिक व्यय की वृद्धि को सीमित कर दिया है, विशेष रूप से सामाजिक क्षेत्रों में।

a. सुधार अवधि में कर कटौती, जिसका उद्देश्य अधिक राजस्व प्राप्त करना और कर चोरी पर अंकुश लगाना है, सरकार के लिए कर राजस्व में वृद्धि नहीं हुई है।

b. टैरिफ में कमी से संबंधित सुधार नीतियों ने सीमा शुल्क के माध्यम से राजस्व बढ़ाने की गुंजाइश कम कर दी है।

c. विदेशी निवेशकों को विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए प्रदान किए गए कर प्रोत्साहन ने कर राजस्व बढ़ाने की गुंजाइश को और कम कर दिया है।

इसका विकासात्मक और कल्याणकारी व्यय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है

### **Effect of reforms on welfare and social justice/ कल्याण और सामाजिक न्याय पर सुधारों का प्रभाव:**

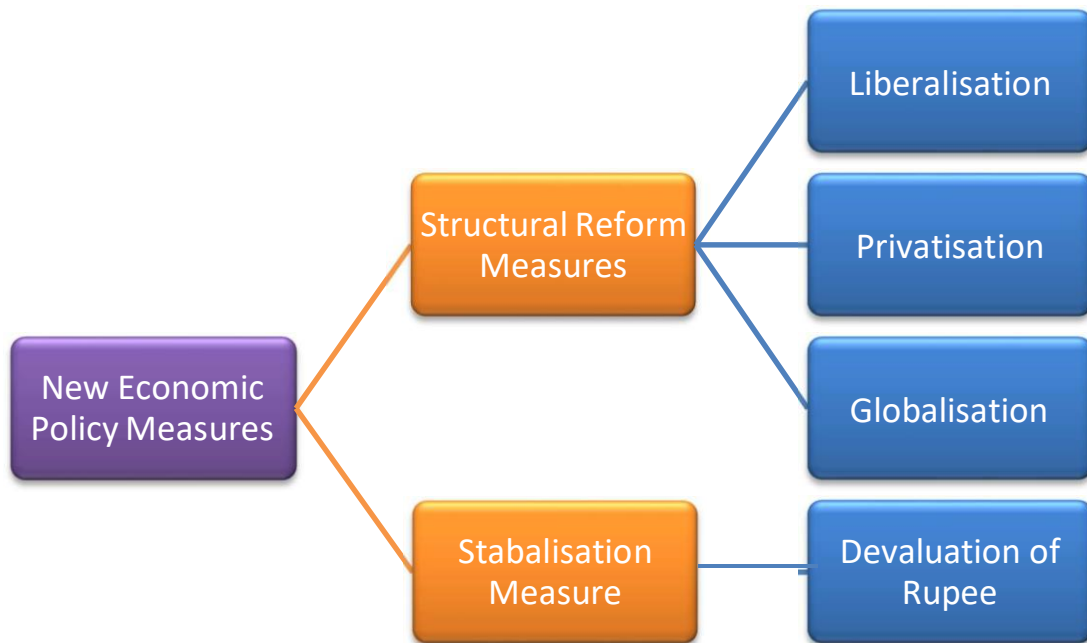
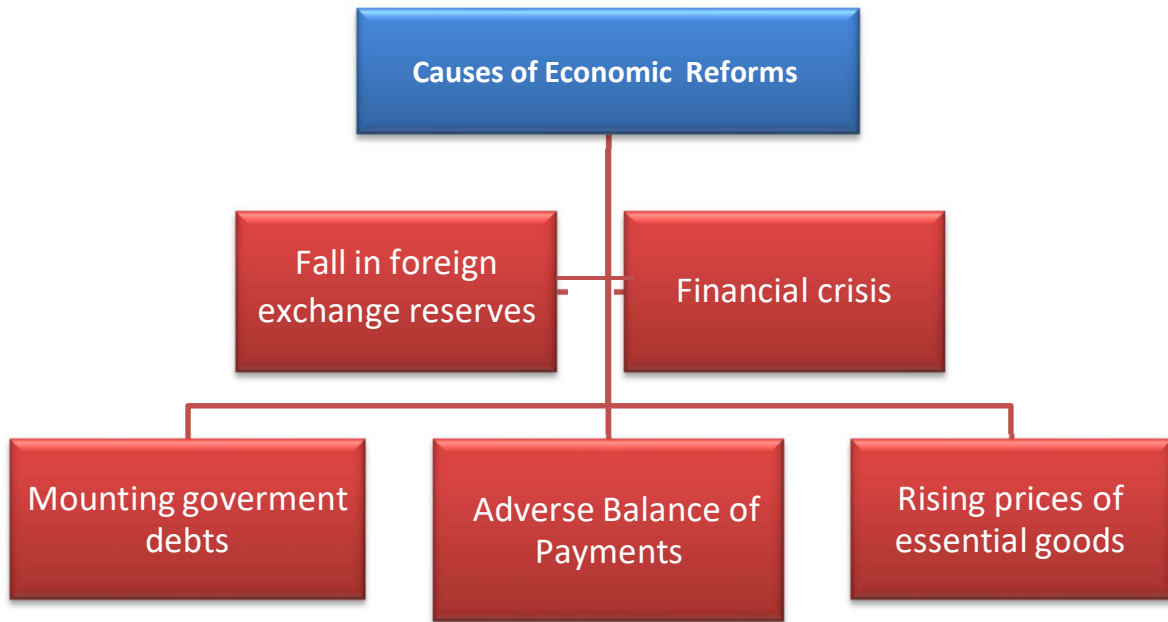
- a. It has increased the income and quality of consumption of only high- income groups and the **growth and employment has been concentrated only in some select areas** in the services sector such as telecommunication, information technology, finance, entertainment rather than vital sectors such as agriculture and industry, which provide livelihoods to millions of people in the country.

इसने केवल उच्च आय वाले समूहों की आय और खपत की गुणवत्ता में वृद्धि की है और विकास और रोजगार केवल सेवा क्षेत्र में कुछ चुनिंदा क्षेत्रों जैसे दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, मनोरंजन के बजाय कृषि और महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में केंद्रित है। उद्योग, जो देश में लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करते हैं।



- b. It has **adversely affected the agricultural sector incomes** due to removal of subsidies and import duties. सब्सिडी और आयात शुल्क को हटाने के कारण कृषि क्षेत्र की आय पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- c. Due to export oriented agricultural strategies and shift towards cash crops, there has been **a rise in price of food grains** affecting the lower income groups adversely. निर्यात-मुखी कृषि रणनीतियों और नकदी फसलों की ओर रुख करने के कारण, निम्न आय वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि हुई है।
- d. It has resulted in the **wiping out of small manufacturing and retail outlets** because of cheap imports. इसके परिणामस्वरूप सस्ते आयात के कारण छोटे विनिर्माण और खुदरा दुकानों का सफाया हो गया है।
- e. Globalisation has **increased the inequalities of income and wealth between the rich skilled and the poor unskilled population.** वैश्वीकरण ने अमीर कुशल और गरीब अकुशल आबादी के बीच आय और धन की असमानताओं को बढ़ा दिया है।

## MIND MAP:



**Liberalisation**

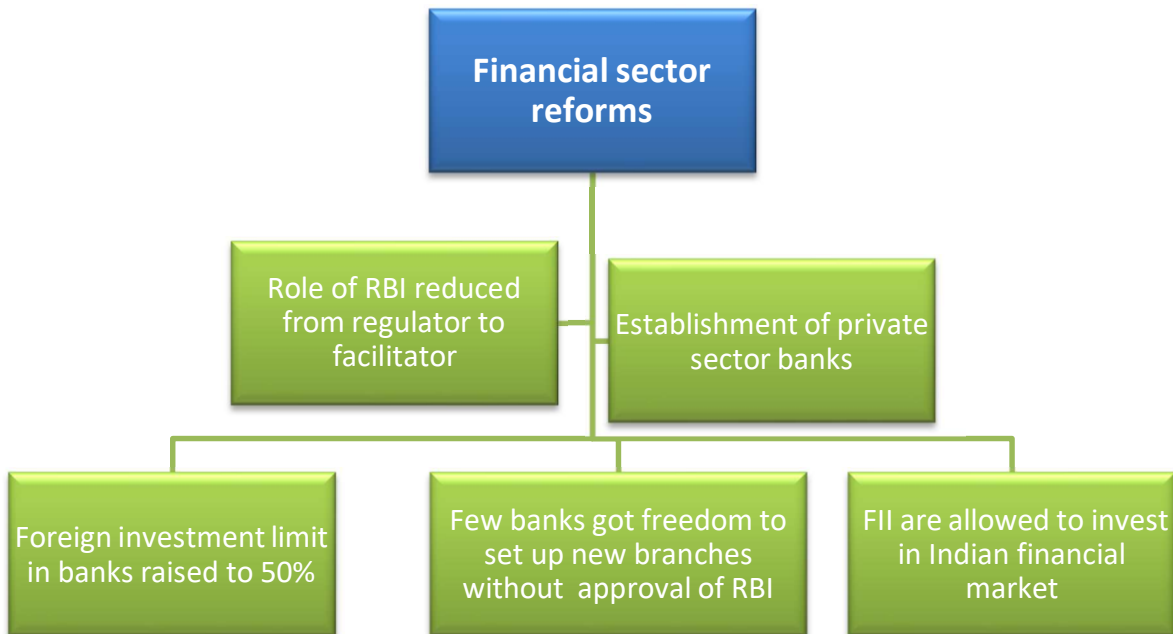
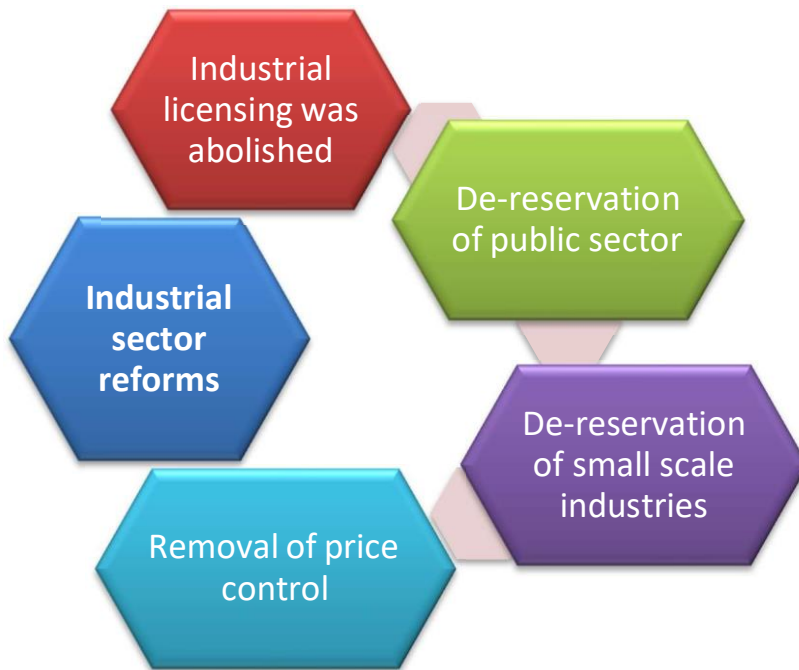
- Involves deregulation and reduction of govt. controls from various sectors of the economy.

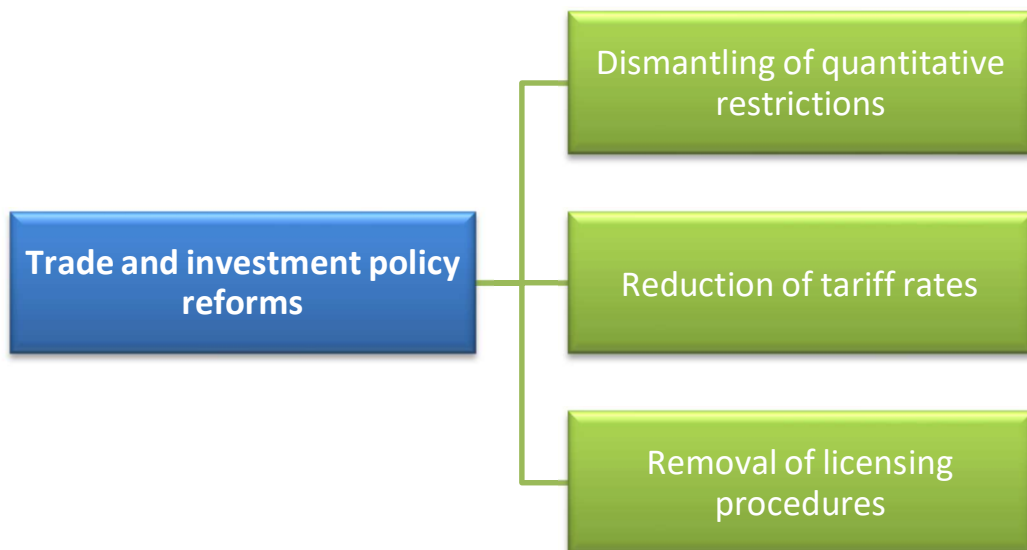
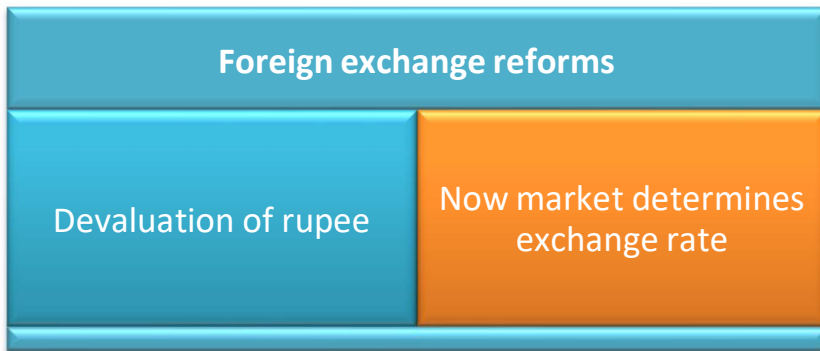
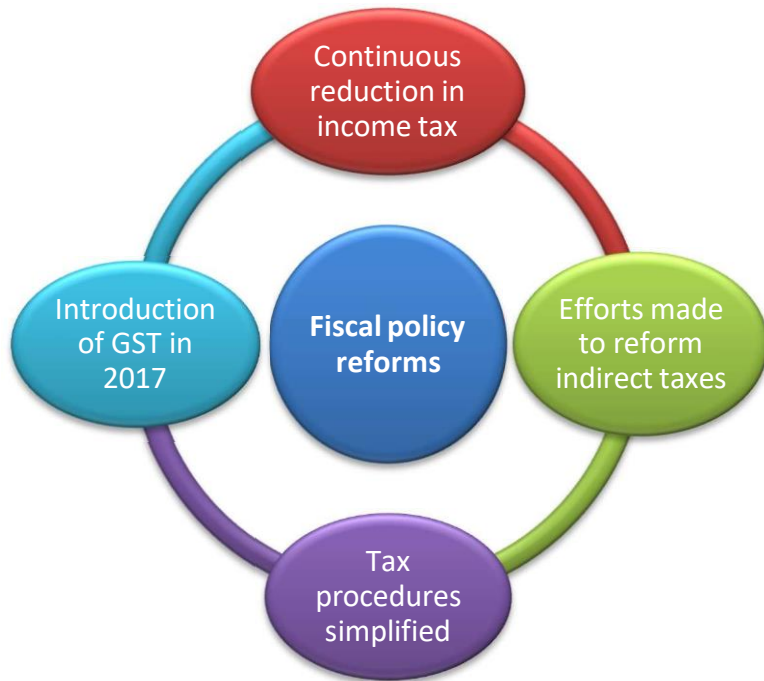
**Privatisation**

- Transfer of ownership, management and control of PSEs to private sector.

**Globalisation**

- Integrating the domestic economy with the world economy.





## CRITICAL APPRAISAL OF ECONOMIC REFORMS

### Positive Effects

### Negative Effects

#### Arguments in favour of NEP

- Increase in GDP growth rate
- Increase in foreign investment (FDI & FII)
- Increase in foreign exchange reserves
- Became a successful exporter of auto parts, IT software etc
- Rising prices kept under control

#### Arguments against NEP

- Increase in GDP without sufficient increase in employment opportunities
- Agricultural growth rate has been decelerating
- Industrial growth has recorded a slowdown
- Disinvestment led to substantial loss to the government
- Fiscal reforms adversely affected govt. tax revenue
- The NEP has increased inequalities; growth has been concentrated in some selected areas

